श्री राजनाथ सिंह: सभापति महोदय, मैंने गुजरात के बारे में बता दिया कि गुजरात को इसके लिए केवल 11 करोड़ रुपए दिए गए । ...(**व्यवधान**)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, my question was simple to how much money was allocated to the State of Gujarat in Phase-I and...

MR. CHAIRMAN: He has answered it. *...(Interruptions)...*

SHRI DIGVIJAYA SINGH: No, he has not answered it. ...(*Interruptions*)... He has not answered it. *...(Interruptions)...* My question is very specific. *...(Interruptions)...* May I repeat, Sir?

माननीय सभापति महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया है कि फेज-I में कितना गुजरात को ऐलोकेशन हुआ, कितना खर्च हुआ और फेज-II में कितना ऐलोकेशन हुआ, कितना खर्च हुआ? महाराष्ट्र और गोवा का मेरा प्रश्न है ही नहीं।

श्री राजनाथ सिंह: श्रीमन्, फेज-I में कितना खर्च हुआ, हर स्टेट के अलग-अलग आंकड़े गुजरात सिहत, फेज-II के लिए कितना ऐलोकेशन हुआ है गुजरात सिहत सभी राज्यों के लिए, मैं समझता हूँ कि इस संबंध में जो भी जानकारी हमारे माननीय सदस्य चाहते हैं, उनको यह जानकारी मैं उपलब्ध करा दूंगा, व्यक्तिगत बातचीत करके भी उपलब्ध करा सकता हूँ, साथ ही साथ लिख कर भी उपलब्ध करा सकता हूँ। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Thank you. *...(Interruptions)...* Answer will be given to you. *...(Interruptions)...* Please.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: सर, मत्री लोग तैयारी से नहीं आते हैं। ...(**व्यवधान**)...

Abating pollution from Daman Ganga River

*126. SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the details of further action taken as on date by Daman and Diu Union Territory Administration in consultation with the State Government of Gujarat to submit a joint comprehensive proposal to the Ministry of Environment and Forests under the National Conservation of River Plan to abate pollution from Daman Ganga river;

(b) Whether the Union Territory Administration approached the State Government of Gujarat in this connection during last six months; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU) : (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

The Union Territory Administration of Daman & Diu received Guidelines from the Ministry of Environment & Forests, New Delhi to prepare a comprehensive plan

for the abatement of pollution in the Daman Ganga River under the National River Conservation Plan and steps have been initiated by the Union Territory Administration to prepare and submit the same to the Ministry of Environment and Forests. In this regard, the National Environment Engineering Research Institute (NEERI), Nagpur has been requested to prepare a comprehensive plan for the abatement of pollution in the Daman Ganga River under the National River Conservation Plan.

The Pollution Control Committee, Union Territory Administration of Daman & Diu has requested the Gujarat Pollution Control Board, Gandhinagar *vide* Letter dated 26.6.2014 for preparation of a joint comprehensive plan for the abatement of pollution in the Daman Ganga River under the National River Conservation Plan.

श्री मनसुख एल. मांडविया: सर, दमन गंगा नदी बारहमासी नदी है और गुजरात और दमन, दोनों के बॉर्डर पर आई हुई यह नदी है, जिसमें बारहों मास पानी रहता है। गुजरात सरकार ने एक योजना बनाई है, जैसे कि तापी, दमन गंगा और पार, इन तीन नदियों को 120 किलोमीटर लिंक केनाल करके हमारे जो ट्राइबल्स क्षेत्र हैं, वहा की इरिगेशन बढ़ाई जाए, वहा के लोगों को सिंचाई की सुविधा मिले और उन नदियों के किनारे दमन की ओर जो इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, उनमें पॉल्यूशन होता है, उस पॉल्यूशन को कम करने के लिए, उन नदियों को पाल्यूशन फ्री करने के लिए भारत सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है?

श्री किरन रिजिजु: चेयरमैन सर, माननीय सदस्य को यह जानकारी दे दी गई है कि नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लांट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरन्मेंट एंड फॉरेस्ट से गाइडलाइंस इश्यू की गई हैं और उनका पालन करने के लिए एक कमिटी का गठन हुआ है, जो कॉम्पेहेंसिव अक्वाप्लान करेगा for abatement of the pollution on river Ganga, जो कि दमन में है। उसके लिए गुजरात सरकार और गुजरात पलूशन कंट्रोल बोर्ड को ऑलरेडी चिट्ठी लिखी गई है कि आप अपने प्रपोजल्स तुरंत भेजिए। हम इस पर ज्वाइंटली काम करेंगे, क्योंकि यह दो राज्यों का मामला है। इसमें यूनियन टेरेट्री ऑफ दमन एंड दीव है एवं दादरा और नागर हवेली है तथा दूसरी गुजरात सरकार है। इसके लिए नेशनल एनवायरन्मेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट (निरी), जो कि नागपुर में है, उसको लिखा गया है और उसने अभी इसकी मंजूरी नहीं दी है, लेकिन उसने इस संबंध में कंप्रेहेंसिव प्लान बनाने की उत्सुकता दिखाई है।

श्री सभापति: ठीक है, दूसरा प्रश्न।

श्री मनसुख एल. मांडविया: सर, मुझे लगता है कि इस परियोजना के लिए उस नदी को और भी अच्छी तरह से पलूशन फ्री करना चाहिए और उसको समय मर्यादा में पलूशन फ्री करके गुजरात के जो ट्राइबल क्षेत्र हैं, उनको नदी लिंकेज करना चाहिए। इससे पहले भी नर्मदा के आधार पर गुजरात जैसे अब तक 16 नदियों को जोड़ चुका है, वैसे ही दमन गंगा, तापी और पार नदी को जोड़ना है और इरिगेशन सुविधा उपलब्ध करानी है। इसलिए मेरा यह स्पेसिफिक प्रश्न है कि क्या उसके लिए स्पेशल ऑफिसर्स की कोई टीम बनाई जाएगी ? इन नदियों को पलूशन फ्री करने के लिए कितने समय में एक्शन लिया जाएगा और इस काम को पूरा किया जाएगा?

श्री किरन रिजिजु: सर, जैसा कि मैंने बताया कि यह स्पेसिफिक क्वेश्चन वहाँ के पलूशन को लेकर है। वापी, जो कि एक मेज़र इंडस्ट्रियल एरिया है, वह गुजरात में पड़ता है और 76 परसेंट

पलूशन वहाँ से होता है । इसके लिए जब तक वे साथ नहीं देंगे, हम अपना प्लान नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो रिवर क्लिनिंग है, वह तो नेशनल प्रोजेक्ट है और हर रिवर को साफ रखने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है। हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि पलूशन अबेटमेंट के लिए पूरा काम करेंगे। हम लोग माननीय सदस्य से भी और जानकारी लेंगे कि इस संबंध में उनके क्या-क्या सजेशंस हैं ।

श्री राजनाथ सिंह: सभापति महोदय, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ । वापी, जो कि गुजरात की एक इंडसि्टयल यूनिट है, वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं । वहाँ की इंडस्ट्रीज़ के कारण ही पहले पलूशन होता था, लेकिन अब वहाँ की स्टेट गवनर्मट ने इस पलूशन को रोकने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए हैं । मैं समझता हूँ कि गुजरात के माननीय सदस्य द्वारा जो चिन्ता और शंका व्यक्त की जा रही है, उनका समाधान जल्द ही हो जाएगा ।

श्री लाल सिंह वडोदिया: माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि जो साबरमती नदी है, उसमें अहमदाबाद के डाउनस्ट्रीम में वउथा तक कई इंडस्ट्रीज़ का पानी जाता है और जब इसके आसपास के किसान इससे पानी लेकर खेती करते हैं, तो उस केमिकलयुक्त पानी के कारण उनकी खेती बहुत बिगड़ जाती है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या उसकी शुद्धिकरण के लिए सरकार कोई योजना बनाएगी?

श्री किरन रिजिजु: सर, यह सवाल जो पूछा गया है, यह इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए मैं इस पर अलग से बाद मैं जानकारी दे सकता हूँ ।

Upgradation of ESI hospital in Goa

*127. SHRI SHANTARAM NAIK : Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state :

(a) whether an Employees' State Insurance (ESI) hospital has been functioning in the State of Goa;

(b) whether the hospital has been recently upgraded and if so, the cost of upgradation;

(c) the funding of Central Government and the State Government respectively; and

(d) the details of ESI scheme, including percentage-wise and year-wise sharing of financial and other burden?

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI NARENDRA SINGH TOMAR) : (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir, the Employees State Insurance (ESI) hospital in Margaon, Goa is providing Outdoor Patient Department (OPD) services and some Indoor Patient Department (IPD) services.

(b) and (c) The up-gradation, including retrofitting/renovation of ESI hospital in Margaon, Goa at a cost of Rs.88 crore is nearing completion. The entire expenditure is born by Employees’ State Insurance Corporation (ESIC).

(d) In addition to ESI hospital in Margaon, there are 12 ESI Dispensaries and 12 Insurance Medical Practitioners (IMPs) under the ESI Scheme in the State of Goa.